

यूपी निवेशकों की पहली पसंद, 540 दिन का काम अब 200 दिन में पूरा निवेशकों को 25 दिनों में दिया जा रहा लेटर आफ कंफर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : पहले जिन परियोजनाओं को शुरू होने में औसतन 540 दिन लगते थे, वे अब करीब 200 दिन में ही क्रियाशील हो रही हैं। वहीं निवेशकों को लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) भी अब 25 दिनों में मिल रहा है, पहले साठ दिन तक लगता था। अब पूर्वांचल में निवेश बढ़ाने के लिए मंडल मुख्यालयों पर रोड शो आयोजित किया जाएगा। बुधवार को कृषि उत्पादन आयुक्त एवं राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (एसएलईसी) के अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय की जानकारी दी गई।

बैठक में उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 की प्रगति, निवेश प्रस्तावों, सब्सिडी वितरण, रोजगार सृजन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की समीक्षा हुई। 25 जिलों से आए 27 नए निवेश प्रस्तावों पर विचार हुआ। इनमें गोरखपुर में बेकरी उत्पाद, बाराबंकी में मल्टीग्रेन फ्लोर मिल,

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति की बैठक
- 24 नए निवेश प्रस्ताव मंजूर पूर्वांचल में निवेश बढ़ाने को मंडल मुख्यालयों पर रोड शो पर जोर

मुरादाबाद में फ्रोजन मटर व सब्जी प्रसंस्करण, कुशीनगर में साल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट, प्रयागराज में डेरी, जौनपुर में पास्ता-नूडल्स, हाथरस व वाराणसी में नमकीन और मिठाई निर्माण इकाइयों के विस्तार सहित कई परियोजनाएं शामिल थीं। सोलर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव भी आए। इनमें 24 प्रस्ताव मंजूर, दो निरस्त और एक शर्तों के साथ स्थगित किया गया।

दीपक कुमार ने कहा कि यह नीति किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का मजबूत माध्यम बन रही है। अधिकारियों को निवेशकों को समयबद्ध और पारदर्शी



सेवाएं देने के निर्देश दिए। इन्वेस्ट यूपी के उद्यमी मित्र सैफ अली रिजवी और दिव्यांश कुमार ओझा को प्रशस्ति पत्र दिया गया। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण नीति से सफल उद्यमियों की कहानियां भी साझा की गईं। अलीगढ़ की एमडी फ्रेश वेज प्राइवेट लिमिटेड को 49.50 लाख रुपये का अनुदान और छह करोड़ रुपये का टर्म लोन मिला। इससे कंपनी का सालाना कारोबार 61 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 150 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। वहीं, रामपुर की आरजे इंडस्ट्रीज को 9.70 करोड़ रुपये का अनुदान मिलने से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को नई रफ्तार मिली।